भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4703
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन अवसंरचना का विस्तार

4703. श्री वी. वैथिलिंगमः
डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का विचार देश में विमानपत्तन नेटवर्क/विमानन अवसंरचना के विस्तार के लिए एक विशेष निवेश नीति तैयार करने का है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है; और
(ग) क्या सरकार का नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने का भी विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): सरकार ने देश में हवाईअड्डा अवसंरचना के विस्तार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा मौजूदा हवाईअड्डों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत असेवित/अल्प-सेवित हवाईअड्डों का विकास/पुनरुद्धार और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से मौजूदा एवं नए हवाईअड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

हवाईअड्डा अवसंरचना का विस्तार, आधुनिकीकरण और विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा यातायात की माँग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विमान परिचालन की सुरक्षा हेतु परिचालन आवश्यकताओं और एयरलाइनों की माँग आदि के आधार पर निष्पादित की जाती है। विकास कार्य भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता के साथ-साथ अपेक्षित विमान परिचालनों के संदर्भ में अन्य सुविधाओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं।
देश में हवाईअड्डा अवसंरचना में सुधार करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पीपीपी भागीदारों ने वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 96,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूँजीगत व्यय किया है। इसमें से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 28,000 करोड़ रुपये से अधिक और शेष पूँजीगत व्यय निजी हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा पीपीपी मोड के तहत किया गया है।

(ग): नोएडा (जेवर), नवी मुंबई, धोलेरा, सिलचर, हीरासर, झारसुगुड़ा, ईटानगर (होलोंगी) और कानपुर हवाईअड्डों पर घरेलू एअर कार्गो सुविधाओं की योजना बनाई गई है।

*****